शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 7 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 09 – 16 फरवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या प्रदेश वित्तीय आपात की ओर बढ़ रहा है? या राष्ट्रपति शासन लगेगा?

शिमला/शैल। 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बन्द किये जाने पर प्रदेश के राजनीतिक हल्कों में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उभरी हैं उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है की कहीं हिमाचल वित्तीय आपात या राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। यह अनुदान बन्द होने पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया वित्त सचिव की इस मुद्दे पर आयी प्रस्तुति से सामने आयी। इस प्रस्तुति से प्रदेश भर में चिन्ता और चिन्तन का माहौल खड़ा हो गया। इस माहौल को देखते हुये सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्तुति सिर्फ एक आकलन है कोई फैसला नहीं। इसके बाद सरकार ने इस पर चर्चा करने के लिये विधानसभा का एक दिन के लिये विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई जिसकी राज्यपाल ने यह कहकर अनुमति नहीं दी कि जब अभी बजट सत्र आ रहा है तो एक दिन के विशेष सत्र की क्या आवश्यकता है। इसके बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आ गया इस सत्र में सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में राजस्व घाटा अनुदान पर वित्त आयोग पर विशेष फोकस कर लिया। लेकिन महामहिम राज्यपाल ने इस अभिभाषण के पैरा तीन से सोलह तक को यह कह कर पढ़ने से मना कर दिया कि इसमें संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं इसलिये वह इसे नहीं पढ़ेंगे। इस तरह राज्यपाल का अभिभाषण दो मिनट एक सेकंड में ही पूरा हो गया। इस तरह वित्त सचिव की प्रस्तुति से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक जो घटा है और उसका आगे क्या प्रभाव हो सकता है इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सरकार ने इस पर लम्बी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है यह चेतावनी मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही दे दी थी। इस स्थिति का दोष पूर्व सरकार के कुप्रबंधन पर डालकर उसके अंतिम छः माह में लिये गये फैसलों को बदल दिया। खराब वित्तीय स्थिति के चलते सरकार कर्ज पर आश्रित होती चली गयी। जब इस सरकार ने पदभार संभाला था तब प्रदेश का कुल कर्जभार 74000 करोड़ था जो आज बढ़कर एक लाख करोड़ से उपर पहुंच गया है और अभी एरियर और महंगाई भत्ते की ही करीब चौदह हजार करोड़ की देनदारियां खड़ी हैं। विभिन्न विभागों की देनदारियां अलग से हैं। सरकार तीन वर्षो से लगातार पूर्व सरकार और केन्द्र पर दोषारोपण करती आ रही है। लेकिन आज तक पूर्व सरकार के एक भी भ्रष्टाचार के मामले को सामने लाकर उस पर कारवाई नहीं कर पायी है। संसाधन जुटाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सरकार तीन वर्षो में मुख्यमंत्री के अनुसार 26000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्रदेश से इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों से भागती रही है। आने वाले पंचायत चुनाव सरकार के सारे दावों का खुलासा सामने रख देंगे। आज फील्ड में न तो सरकार के काम दिख रहे हैं और न ही कार्यकर्ता। यह स्थिति हो गयी है।

इस वस्तु स्थिति में जब राजस्व घाटा अनुदान बन्द होने का सच सामने आया है तो सरकार के हाथ पैर फूलने पर चर्चा आवश्यक हो जाती है। राजस्व घाटा अनुदान बन्द होगा यह पिछले वित्त आयोग की रिपोर्ट में ही स्पष्ट अंकित था। यह अनुदान 31 मार्च 2026 तक ही रहेगा यह स्पष्ट था। फिर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी 2025 में आ गयी थी तब सरकार इस पर सचेत क्यों नहीं हुई? जो अधिकारी वित्त आयोग के पास प्रदेश का पक्ष रखते रहे हैं क्या सरकार उनको जनता के साथ सांझा करेगी? राजस्व घाटा अनुदान कोई शाश्वत अधिकार नहीं है जिसे अदालत के माध्यम से बहाल करवाया जा सके। यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया एक प्रावधान है। इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुदान किसी भी सूरत में बहाल नहीं होगा। इस मुद्दे पर यदि विपक्ष भी सरकार के साथ मिलकर दिल्ली में गुहार लगाने चला तो फिर भी इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े होंगे उसके संकेत जयराम ठाकुर के उस बयान से सामने आ गये हैं जिसमें वह सरकार से उस कांग्रेस नेता के

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सभी विभागों में 60 वर्ष नहीं है

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। लेकिन 2001 में एक अधिसूचना के तहत इसमें बदलाव करते हुये यह कह दिया गया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 को या इसके बाद नियुक्त हुये हैं या नियमित हुये हैं उनकी सेवानिवृत्ति 58 वर्ष पूरा होने पर हो जायेगी। इस अधिसूचना को एक नारो देवी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इस चुनौती पर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस अधिसूचना को भेदभाव पूर्ण करार देते हुए सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत किये जाने का फैसला दिया है। 2024 में आये इस फैसले पर सुक्खू सरकार ने भी इसी आश्य के आदेश जारी कर दिये। लेकिन सरकार के यह आदेश अभी तक सारे विभागों और कार्यालयों तक नही पहुंचे हैं। ऊना में जल शक्ति विभाग में तो इन आदेशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हो रही है। परन्तु इसी जिले के शिक्षा विभाग में आज तक इस आश्य के कोई आदेश नहीं पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग में यह असमजस बनी हुई है कि वह अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किस आयु सीमा में सेवानिवृत्त करें। जल शक्ति विभाग में 60

शेष पृष्ठ 8 पर.....

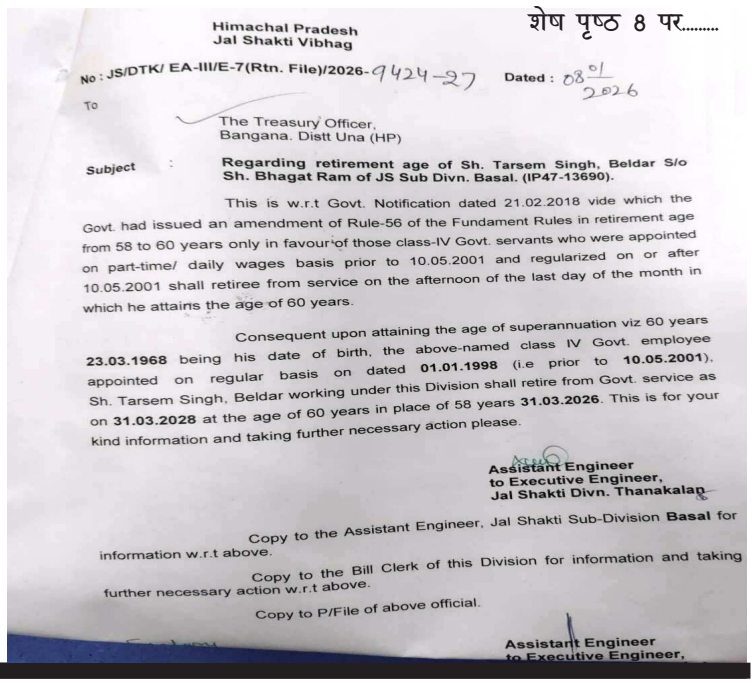

Himachal Pradesh
Jal Shakti Vibhag

No : JS/DTK/ EA-III/E-7(Rtn. File)/2026-9424-27 Dated : 08/01/2026

To

The Treasury Officer,
Bangana. Distt Una (HP)

Subject : **Regarding retirement age of Sh. Tarsem Singh, Beldar S/o Sh. Bhagat Ram of JS Sub Divn. Basal. (IP47-13690).**

This is w.r.t Govt. Notification dated 21.02.2018 vide which the Govt. had issued an amendment of Rule-56 of the Fundament Rules in retirement age from 58 to 60 years only in favour of those class-IV Govt. servants who were appointed on part-time/ daily wages basis prior to 10.05.2001 and regularized on or after 10.05.2001 shall retiree from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 60 years.

Consequent upon attaining the age of superannuation viz 60 years **23.03.1968** being his date of birth, the above-named class IV Govt. employee appointed on regular basis on dated **01.01.1998** (i.e prior to **10.05.2001**), Sh. Tarsem Singh, Beldar working under this Division shall retire from Govt. service as on **31.03.2028** at the age of 60 years in place of 58 years **31.03.2026**. This is for your kind information and taking further necessary action please.

Assistant Engineer
to Executive Engineer,
Jal Shakti Divn. Thanakalan

Copy to the Assistant Engineer, Jal Shakti Sub-Division **Basal** for information w.r.t above.

Copy to the Bill Clerk of this Division for information and taking further necessary action w.r.t above.

Copy to P/File of above official.

Assistant Engineer
to Executive Engineer,

सर्वदलीय बैठक से भाजपा का वॉकआउट निंदनीय: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित सर्वदलीय बैठक

में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद किए जाने के प्रदेश पर संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को राज्य की आर्थिकी के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि यदि राजस्व घाटा अनुदान वापस लिया जाता है तो इसका सीधा असर विकास कार्यों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक को बीच में छोड़कर जाने के लिए भाजपा की कड़ी आलोचना की और इसे प्रदेश हितों के प्रति असंवेदनशील रवैया बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है और राज्य के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय राजनीतिक लाभ-हानि का आकलन कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के साथ-साथ सीपीआई (एम) आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। उनके अनुसार, भाजपा नेता जनता के दबाव में बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन बीच में ही बाहर चले गए, जिससे उनका रुख और अधिक संदिग्ध हो गया।

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटा अनुदान के रूप में लगभग 54,000 करोड़ रुपये और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक केवल 17,000 करोड़ रुपये ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद सतर्क वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान राज्यों का संविधानिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संतुलित करना है। यह व्यवस्था वर्ष 1952 से लागू है और विशेष परिस्थितियों वाले राज्यों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में सहायक रही है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को यह अहसास है कि केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करना उचित कदम नहीं है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से अपना स्पष्ट रुख रखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी दल का नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के अधिकारों का है।

साल 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य ने विशेष राहत पैकेज की मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, तब भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया था। उन्होंने इसे हिमाचल विरोधी रवैया करार देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और ऐसे व्यवहार को कभी माफ नहीं करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी भाजपा के बैठक से बाहर जाने के कदम की निंदा की। बैठक में अन्य दलों ने राज्य सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की।

पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सभी राजनीतिक दलों से प्रदेश हित में आम सहमति बनाने का आहवान किया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि डॉ. राजेश चानना ने कहा कि सीमित संसाधनों वाले हिमाचल जैसे राज्य के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग अनिवार्य है। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि ने भी कोविड-19 और हाल की प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य पर बढ़े वित्तीय दबाव का उल्लेख करते हुए एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर राज्य सरकार हर स्तर पर अपनी बात मजबूती से रखेगी और हिमाचल के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। शिव प्रताप शुक्ल तथा सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात है और महाशिवरात्रि यहां मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रदेश के लोग प्राचीन काल से ही पारंपरिक उल्लास और आस्था के साथ महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कामना की कि यह पर्व आपसी भाईचारे को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार करे।

7.41 करोड़ रुपये की लागत से कांगड़ा में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन

शिमला/शैल। कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना नड्डी, धौलाधार घाटी में स्थापित की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपये है।

एशिया की सबसे लंबी बताई जा रही इस जिपलाइन में चार स्टेशन -गल्लू (प्रारंभिक बिंदु), बल गांव, नड्डी और मैगी प्वाइंट खड्ड (समापन बिंदु) निर्धारित किए गए हैं। परियोजना को 36 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह जिपलाइन नड्डी व्यू प्वाइंट के पास विकसित की जाएगी, जो धौलाधार पर्वतमाला के विहंगम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सरकार के अनुसार, परियोजना से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने कांगड़ा को 'पर्यटन राजधानी' का दर्जा देते हुए पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

कुल्लू में लहसुन व मसाला फसलों की व्यावसायिक खेती पर संगोष्ठी

शिमला/शैल। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बजौरा जिला कुल्लू में कुल्लू में लहसुन एवं मसाला फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर दो दिवसीय जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना के अंतर्गत किया गया।

संगोष्ठी में कुल्लू जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक खेती पद्धतियों, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तथा उन्नत कृषि प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से लहसुन एवं मसाला फसलों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाना था।

कृषि विज्ञान केंद्र कुल्लू के हेड डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुल्लू घाटी की कृषि-जलवायु परिस्थितियां लहसुन और मसाला फसलों की व्यावसायिक खेती के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने उन्नत किस्मों, प्रमाणित बीजों, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा बाजारोन्मुख उत्पादन प्रणाली अपनाने पर बल दिया।

बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष डॉ. एन.के.भरत ने गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मसाला फसलों की बढ़ती मांग को देखते हुए बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना आवश्यक है। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सह-निदेशक डॉ. बी.एस. ठाकुर ने अनुसंधान प्रसार किसान समन्वय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अशोक ठाकुर ने लहसुन व अन्य मसाला फसलों में प्रमाणित बीज उत्पादन और चयनित एक्जॉटिक मसालों की संभावनाओं पर जानकारी दी। तकनीकी सत्रों में उत्पादन तकनीक, कीट एवं रोग प्रबंधन, मृदा एवं जल प्रबंधन तथा फसलोपरांत प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने व्यावहारिक जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान मसाला फसल उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को सम्मानित किया गया।

डिजिटल जनगणना राष्ट्रीय महत्व की गतिविधि, पूर्ण समन्वय से करें कार्य: मुख्य सचिव

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जनगणना 2027 को डिजिटल मोड में संचालित

किए जाने को एक सराहनीय और ऐतिहासिक पहल बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इसे राष्ट्रीय महत्व की गतिविधि मानकर पूर्ण निष्ठा, समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। वे प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकान गणना' की तैयारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

प्रदेश सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के सदस्य, सभी मंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, श्रीमती दीप शिखा शर्मा ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन के उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि जनगणना 2027 राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया और विकास योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य के बीच इस राष्ट्रीय अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए।

सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं राज्य नोडल अधिकारी राजेश शर्मा ने विभिन्न विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में जनगणना के डिजिटल संचालन, डेटा संकलन प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

केवल पंजीकृत नर्सरियों से ही खरीदें फल पौधे:बागवानी विभाग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने किसानों और बागवानों से अपील की है कि वे फलदार पौधे केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी नर्सरियों से ही खरीदें। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कुछ नर्सरी संचालक बिना उचित दस्तावेजों के अन्य राज्यों से अवैध रूप से सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम आदि के पौधे लाकर बेच रहे हैं। ऐसे पौधों की गुणवत्ता और स्रोत प्रमाणित नहीं होता, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान और बागानों में रोग फैलने का खतरा रहता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने हिमाचल प्रदेश फल नर्सरी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2015 तथा नियम, 2020 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना वैध लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, स्रोत प्रमाण-पत्र और फाइटोसैनिटरी दस्तावेजों के पौधे बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने किसानों से कहा कि पौधे खरीदते समय नर्सरी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र अवश्य देखें और बिना बिल के पौधे न लें। साथ ही, गैर-पंजीकृत नर्सरियों या संदिग्ध बिक्री की सूचना नजदीकी बागवानी अधिकारी को दें, ताकि अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य में पहली बार शराब ठेकों और टोल बैरियरों की ई-नीलामी

शिमला/शैल। हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा आबकारी शराब ठेकों तथा प्रवेश टोल बैरियरों का आवंटन पहली बार पूर्णत: ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ई-नीलामी इकाई-वार आयोजित होगी और प्रत्येक इकाई में शामिल शराब ठेकों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आवेदक घर या कार्यालय से ही डिजिटल माध्यम से बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि सभी आवेदकों के लिए मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ नामित ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जमा की गई ऑनलाइन बोलियां ही स्वीकार की जाएंगी। पोर्टल का लिंक विभाग की वेबसाइट www.hptax.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने कहा कि बोलीदाताओं को भागीदारी से पूर्व आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रियाएं और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का अध्ययन करना चाहिए। अद्यतन जानकारी और अधिसूचनाओं के लिए विभागीय वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। सहभागिता सुगम बनाने के लिए विभिन्न जोन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

टोल टैक्स व आबकारी नीति को मंजूरी, 1,617 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजना स्वीकृत

शिमला/शैल। शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे आगामी

वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्रबंधन की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने महिला होम गार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' में संशोधन करते हुए विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर और बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' को लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए कुल 600 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत और ड्राइंग शिक्षकों के 150-150 पद शामिल हैं। इन पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। राज्य के 31 बालक एवं बालिका विद्यालयों को सह-शिक्षा विद्यालयों में विलय करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही 777 अतिरिक्त विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए चौपाल में वॉलीबॉल छात्रावास, शिलाई में कबड्डी छात्रावास, जुब्बल में बॉक्सिंग खेल सुविधा तथा मोरसिंघी (बिलासपुर) में हैंडबॉल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे, जबकि लुहणू खेल छात्रावास की क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 बिस्तर कर दी गई है। चंबा जिले में डिस्टिल ग्लोबल स्किल्स एवं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जो कौशल विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालयों, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 1,617.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना है ताकि मरीजों को उपचार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। कमला नेहरू अस्पताल शिमला, मातृ एवं शिशु अस्पताल सुंदरनगर, नागरिक अस्पताल नूरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, नागरिक अस्पताल भोरंज के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और बिलासपुर की जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन एवं अनुरक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिससे उपकरणों का नियमित रखरखाव और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य विभाग में फार्मेसी अधिकारी के 40, सहायक स्टाफ नर्स के 150, रेडियोग्राफर के 30 तथा अन्य विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। नूरपुर, बद्दी और ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की जाएगी।

प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भर्ती निदेशालय में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 190 और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 151 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई है। राजस्व विभाग में भी कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के तीन पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में आठ सफाई कर्मचारी तथा सैनिक कल्याण विभाग में पांच वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। सिरमौर जिले में लोक निर्माण विभाग के मंडलों का विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप पुनर्गठन किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के लिए रोड ड्रेनेज नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे सड़कों की मजबूती बढ़ेगी, रखरखाव लागत कम होगी और हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही बिटुमिनस और फ्लेक्सिबल सड़कों पर ब्लों की मरम्मत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सालय कोटखाई को उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 का प्रारूप तैयार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई है। समग्र रूप से मंत्रिमंडल के ये निर्णय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में व्यापक पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। अब इन फैसलों का वास्तविक प्रभाव उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों के शिक्षकों का मूल कैडर अधिकार सुरक्षित रखा जाये:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये हैं कि सीबीएसई से संबद्ध किए जा रहे सरकारी स्कूलों में चयनित शिक्षकों का

उनके मूल कैडर में अधिकार (लियन) सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनकी पदोन्नति और सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। पहले चरण में 99 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है, जबकि शेष स्कूलों के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।

उन्होंने सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों में आंशिक राहत देने और शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के निर्देश भी दिए। इन स्कूलों का अलग लोगो और वर्दी निर्धारित की जाएगी।

बैठक में 'नो मोबाइल फोन नीति' की समीक्षा भी की गई, जो एक मार्च से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी औपचारिकताएं पूरी करने और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरस मेले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सशक्त आधार:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। इंदिरा मार्केट में आयोजित सरस मेले का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश

अग्निहोत्री ने किया। उद्घाटन के उपरान्त उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरस मेला ग्रामीण आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण तथा स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों के प्रोत्साहन का सशक्त मंच है। ऐसे आयोजन न केवल ग्रामीण उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने आमजन से आहवान किया कि वे अधिकाधिक संख्या में मेले में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करें।

मंडी सरस मेला 16 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सहित कुल 14 राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित हुई है। प्रदेश के सभी 12 जिलों तथा मंडी जिले के 14 विकास खंडों के स्वयं सहायता समूह इसमें भाग ले रहे हैं। मेले में कुल 96 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिनमें 15 स्टॉल स्थानीय व्यंजनों के लिए समर्पित हैं। शेष स्टॉलों पर हैंडलूम, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद तथा विविध ग्रामीण उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

यह मेला स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से क्षेत्रीय विरासत की झलक भी देखने को मिल रही है, जिससे यह मेला व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक संगम का रूप ले चुका है। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की सक्रिय भागीदारी मेले की सफलता को दर्शा रही है।

इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर, जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष चंपा ठाकुर, उपायुक्त अपूर्व देवगन, जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने 32 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

शिमला/शैल। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर

जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में लगभग 32 करोड़ रुपये लागत की सात विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 1.44 करोड़ रुपये की लागत से सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ के लिए कार्यालय-सह-आवासीय भवन, 1.98 करोड़ रुपये से नोहरी में उप-तहसील भवन, 5.74 करोड़ रुपये से थानी-थामनी-खरीमू सड़क, 4.73 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना लाना भलटा लोह (ग्राम पंचायत लाना भलटा) तथा 1.66 करोड़ रुपये से बडगला मार्ग होते हुए राजगढ़-यशवंत नगर सड़क का लोकार्पण किया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने 14.13 करोड़ रुपये की लागत से चाबयोगा से सालमु के बीच गिरी नदी पर वाहन योग्य पुल तथा 2.15 करोड़ रुपये की लागत से राजगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग कॉलोनी में टाइप-2 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

टारना मंदिर में उपमुख्यमंत्री ने लिया कमरूनाग और माता श्यामाकाली का आशीर्वाद

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के पावन अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने टारना मंदिर पहुंचकर मंडी जनपद के आराध्य देव टारना मंदिर में विराजमान देव कमरूनाग का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने माता श्यामाकाली की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

इसके उपरांत उपमुख्यमंत्री ने बाबा भूतनाथ मंदिर तथा भीमाकाली मंदिर में भी पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव में पधारे समस्त देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे तथा हिमाचल निरंतर उन्नति, शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता रहे।

सत्य किसी भी सामूहिक विनाश के हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली है .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पर आचरण क्या संकेत है?

इस समय हिमाचल सरकार के सामने राजस्व घाटा अनुदान बहाल करवाने तथा राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने और पंचायत चुनाव में पार्टी तथा हाईकमान की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौतियां एक साथ सामने आ गयी हैं। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को और पंचायती चुनाव मई के अन्त तक होने हैं। क्या सरकार इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पायेगी यह सवाल हर आदमी के सामने खड़ा है। क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार होते हुये भी राज्यसभा भाजपा छीन कर ले गयी थी। भाजपा इस बार भी चुनाव लड़ेगी और जब भाजपा चुनावी मैदान में होगी तो कांग्रेस हार की आशंका से मुक्त नहीं हो सकती। पार्टी और सरकार के भीतर जो राजनीतिक परिस्थितियां पिछले चुनाव के दौरान थी वह शायद इस बार पहले से ज्यादा मुखर है। पिछली बार कांग्रेस का संगठन था परन्तु इस बार यह संगठन जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। पिछली बार कांग्रेस के नाराज लोगों ने अपनी नाराजगी हाईकमान तक पहुंचाने के लिये चिट्ठी पत्र का माध्यम चुना था। इस बार सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने खुलेआम अफसरशाही पर निशाना साधते हुये अपरोक्ष में मुख्यमंत्री और हाईकमान दोनों को एक साथ इंगित कर दिया है। ऐसे ही वातावरण में वीरभद्र कांग्रेस के गठन की संभावनाएं भी गंभीरता से तैरना शुरू हो गई है। क्योंकि अनचाहे ही यह संदेश और संकेत खुलेआम चले गये हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र समर्थकों को किनारे लगाते चले आ रहे हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर और मण्डी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसियों के क्षेत्र से जितने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तजापोशियां दी गयी हैं उनसे अनचाहे ही कई मंत्रियों और दूसरे प्रभावी नेताओं के सामने इन नियुक्तियों के माध्यम से समानान्तर सत्ता केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। वैसे भी इन ताजपोशियों में क्षेत्रीय संतुलन को लगभग नजरअन्दाज कर दिया गया है। पिछली बार राज्यसभा सीट इस कारण हारी थी क्योंकि उम्मीदवार प्रदेश से बाहर का व्यक्ति था। इस बार भी यदि पिछले ही क्रम को दोहराया गया तो पहले जैसा ही आचरण होने की संभावनाएं शायद बढ़ जायेगी। फिर पंचायत चुनाव टालने की सरकार ने हर संभव कोशिश कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय तक दस्तक दे दी। लेकिन अन्त में अदालत के फैसले से चुनाव करवाने की बाध्यता आ गयी। इससे भी सरकार के पक्ष में कोई सकारात्मक संदेश नहीं गया। इसी वस्तुस्थिति में राजस्व घाटा अनुदान बन्द होने का फैसला आ गया। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने जो भी पक्ष रखा उसका कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन इसी संकट के बीच जब एपीएमसी की गाड़ी खरीद का प्रकरण सामने आ गया तो सरकार के प्रति जन सहयोग और सहमति पर स्वत: ही प्रश्न चिन्ह लग गये। सरकार द्वारा की गई सारी राजनीतिक ताजपोशियां चर्चा में आ गयी। क्योंकि इस आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक ताजपोशी पाये एक भी मित्र ने अपने वेतन भत्ते त्यागने या पद छोड़ने की पेशकश नहीं की। इसी कारण सरकार की आज तक की सारी कार्यप्रणाली और फैसले जन समीक्षा का केन्द्र बन गये हैं। जिन अफसरशाहों को उनके दिल्ली से मधुर संपर्क को और रिश्तों के नाम पर सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार और पुन: नियुक्तियों से नवाजा गया था वह भी इस आर्थिक संकट में कोई ठोस सहायता नहीं दे पाये। इस समय कुल मिलाकर जो परिस्थितियां निर्मित हो गयी हैं उनसे जो वातावरण बन चुका है उससे राजनीतिक खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह स्वभाविक है कि जो लोग सरकार की कार्य प्रणाली पर मत भिन्नता रखते हैं उन्हें अपने रोष को हवा देने का पूरा-पूरा संयोग खड़ा हो गया है। क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में वित्त आयोग पर आई टिप्पणियों को नहीं पढ़ा है उसका संकेत और संदेश बहुत दूरगामी है यह तय है। इस परिदृश्य में यह संभावना बहुत प्रबल हो गयी है कि इस सब का प्रतिफल सहज नहीं होगा। इसे आने वाले संकट का संकेत मानना ही होगा।

बाबरी मस्जिद का मामला सुलझाया जा चुका है, कृपया उस घाव को कुरेद कर सामाजिक सौहार्द न बिगाड़िए

गौतम चौधरी

बाबरी मस्जिद मामला सुलझ चुका है। जिस स्थान पर मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कथित तौर पर एक मस्जिद तामीर करवाई उस स्थान पर आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। दअरसल, उस स्थान को लेकर हिन्दू पक्षकारों का दावा था कि मीर बाकी ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर, जहां पहले से एक मंदिर बना था उसे तोड़ कर वहां मस्जिद बनवाई थी। खैर मामला लंबा चला और उस स्थान पर कई संघर्ष भी बताए जाते हैं। हाल के वर्षो में भी संघर्ष देखे गए। बाबरी मस्जिद विवाद में हजारों लोगों ने जान गवाई और देश में ही नहीं पड़ोस के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी बड़े-बड़े दंगे हुए। खैर, वर्ष 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि और ढांचे का निराकरण कर दिया। मामला सुलक्ष गया। दोनों पक्ष मान गए। बाबरी ढांचे के स्थान पर राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक वैकल्पिक स्थल पर नई मस्जिद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी। हालांकि मस्जिद का शिलान्यास नहीं हो पाया है लेकिन उस दिशा में काम चालू बताया जा रहा है। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है, जिससे राजनीतिक माहौल ही नहीं गरमा है अपितु एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द बिगडने की पूरी संभावना है।

इस मामले को लेकर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला पहले सुना चुकी है। बावजूद इसके 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के नेता हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में तथाकथित 'नई बाबरी मस्जिद' की आधारशिला रखी और इसे 1992 में ढहाई गई मस्जिद की प्रतिकृति बताया। यह कार्यक्रम उसी तारीख को हुआ जिस दिन मस्जिद का विध्वंस हुआ था और एक दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिर भी यह कदम धार्मिक आस्था से अधिक राजनीतिक अस्तित्व बचाने का प्रयास प्रतीत होता है, खासकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से उनके निलंबन और नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के गठन के बाद।

कबीर का राजनीतिक जीवन दल-बदल से भरा रहा है। 2011 में कांग्रेस विधायक चुने जाने के बाद वे टीएमसी में गए, फिर 2018 में भाजपा में शामिल हो गए। बाद में 2021 में फिर टीएमसी में लौटकर चुनाव जीते। विकास कार्यो की उल्लेखनीय उपलब्धियों के अभाव में उन्होंने भावनात्मक धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की है। बताया जाता है कि समर्थकों ने ईंटें और धन दान किया लेकिन यह परियोजना आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर शुरू की गई बतायी जा रही है। मुस्लिम बाहुल जिले में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह कदम वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति जैसा दिखता है।

इसी तरह हैदराबाद में मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने भी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर 'स्मारक मस्जिद' बनाने की घोषणा की है। ऐसे प्रयास उस समय साम्प्रदायिक भावनाओं को फिर से भड़का सकते हैं, जब अयोध्या विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। 1528 में निर्मित बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ढहा दी गई थी, जिसके बाद देशभर में दंगे हुए और दशकों तक मुकदमेबाजी चली। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए हिन्दू पक्षकारों को सौंपते हुए अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक भूमि मस्जिद के लिए देने का निर्देश दिया। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ विवाद का अंत हो गया।

हालांकि मस्जिद के लिए दी गई भूमि पर 2026 की शुरुआत तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। प्रशासनिक देरी और संसाधनों की कमी इसका कारण बताया जा रहा है। ऐसे में वैधानिक रूप से आवंटित भूमि पर निर्माण के बजाय अन्य स्थानों पर प्रतिकृति बनाना साम्प्रदायिक संवेदनाओं को फिर से उभार सकता है। 6 दिसंबर अब भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील तारीख है। इतिहास बताता है कि लंबे आंदोलन ने समाज को ध्रुवीकृत किया। आज भारतीय मुसलमान शिक्षा, रोजगार और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रतीकात्मक परियोजनाएं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। राजनीतिक लाभ के लिए पुराने घावों को कुरेदना समाज में विभाजन बढ़ा सकता है। बाबरी प्रकरण से यह सीख मिलती है कि कानूनी फैसले को स्वीकार कर शांति और विकास पर ध्यान देना ही उचित मार्ग है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब प्राथमिकता सामाजिक सद्भाव और प्रगति होनी चाहिए। प्रतिकृति निर्माण के प्रयास अतीत की स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं, जबकि भारत का बहुलतावादी लोकतंत्र साझा भविष्य के निर्माण से ही मजबूत होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिक्रिया केवल विवाद को जन्म देता है। इससे विकास की संभावना क्षीण होती है। किसी चिंतक ने कहा है कि यदि आप अतीत पर गोली दागेंगे तो भविष्य आप पर गोले बरसाएगा। इससे हमारा वर्तमान खराब होगा। सह अस्तित्व में ही प्रगति प्रस्फुटित होता है। बाबरी विवाद को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के साथ ही यह विवाद समाप्त हो चुका है। हां, अयोध्या के वैकल्पिक भूमि पर सरकार को सहयोग कर मस्जिद बनवाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। दूसरी ओर जो लोग अपनी राजनीति चमकाने मात्र के लिए इस प्रकार की घोषणा कर समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: भारत की भविष्य की गतिशीलता की मजबूत नींव

प्रो. मनोज चौधरी
कुलपति
गति शक्ति विश्वविद्यालय

परिवहन और लॉजिस्टिक्स (आवागमन और माल ढुलाई) देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख इंजन हैं। हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, जो भी यात्रा करते हैं और जिन शहरों में रहते हैं, सब कुछ लोगों, सामान और सेवाओं की सुचारु आवाजाही पर निर्भर करता है।

लेकिन पूरी दुनिया में, और खास तौर पर भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में, परिवहन व्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे शहरों में जाम, सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी, ईंधन की बढ़ती कीमतें, प्रदूषण और जटिल होती सप्लाई चेन।

पुरानी योजना और काम करने की पारंपरिक पद्धतियां अब इतनी बड़ी और जटिल व्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस एक बड़ा बदलाव लाने वाली तकनीक बनकर सामने आए हैं, जो यह बदल रहे हैं कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम कैसे बनाए जाएं, कैसे चलाए जाएं और कैसे बेहतर बनाए जाएं।

एआई और डेटा साइंस से परिवहन में बड़ा बदलाव

आज की परिवहन व्यवस्था से बहुत बड़ी मात्रा में डेटा बनता है – जैसे ट्रैफिक सेंसर, जीपीएस वाले वाहन, इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम, टिकटिंग प्लेटफॉर्म, निगरानी कैमरे, मौसम की जानकारी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इस कच्चे और तेज़ी से आने वाले भारी डेटा को उपयोगी जानकारी में बदल देते हैं। इससे परिवहन सिस्टम पहले से अंदाज़ा लगाने वाला, हालात के अनुसार बदलने वाला और ज्यादा मजबूत बन जाता है।

यह बदलाव खास तौर पर भारत में साफ दिखाई देता है, जहां बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं यह तय कर रही हैं कि लोगों की आवाजाही और सामान की ढुलाई की योजना कैसे बनाई जाए और कैसे चलाई जाए।

शहरों और हाईवे पर यातायात में अब मशीन लर्निंग पर आधारित इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रैफिक और टोल संचालन का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है

फास्टैग, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इससे वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक की भीड़ और रास्तों के इस्तेमाल से जुड़ा रियल – टाइम डेटा मिलता है। यह डेटा जाम का विश्लेषण करने, ट्रैफिक को बेहतर तरीके से संभालने और सही आधार पर नई सड़क व ढांचा योजना बनाने में मदद करता है।

इसी तरह कई भारतीय शहरों में एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाए गए हैं, जो कैमरों और सेंसर से मिलने वाले लाइव डेटा के आधार पर सिग्नल का समय ठीक करते हैं, बेवजह रुकने का समय घटाते हैं और चौराहों की सुरक्षा बढ़ाते हैं।

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) जैसे डेटा प्लेटफॉर्म एआई आधारित फैसलों की दिशा में बड़ा कदम हैं। यह प्लेटफॉर्म रेलवे, बंदरगाह, सड़क परिवहन और कस्टम्स का डेटा एक साथ जोड़कर भारत के लॉजिस्टिक्स सिस्टम की एक साझा डिजिटल रीढ़ तैयार करता है।

इस पर एआई और उन्नत विश्लेषण से मांग का अनुमान, बेहतर रूट चुनना और सप्लाई चेन में अटकाव वाले स्थानों की पहचान करना आसान होता है। ये सुविधाएं खास तौर पर तब बहुत जरूरी हो जाती हैं, जब देश में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि लॉजिस्टिक्स लागत घटे और सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बन सके।

नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एआई और डेटा साइंस की भूमिका को और मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर चिनाब ब्रिज जैसी बड़ी परियोजनाओं में सुरक्षा और लंबे समय तक भरोसेमंद संचालन के लिए सेंसर से मिलने वाला डेटा, ढांचे की सेहत की निगरानी और पहले से अंदाज़ा लगाने वाली तकनीक का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वंदे भारत ट्रेनों में बहुत तेजी से और बड़ी मात्र में डेटा मिलता है, जिससे एआई समय – सारणी बेहतर बनाने, बिजली की खपत घटाने, यात्रियों की भीड़ को संभालने और रखरखाव की योजना बनाने में मदद करता है।

जैसे – जैसे भारत हाई – स्पीड रेल कॉरिडोर की ओर बढ़ रहा है, वैसे – वैसे डेटा के आधार पर नियंत्रण, रियल – टाइम निगरानी और पहले से मरम्मत की तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाएगा, ताकि तेज रफ्तार में भी सुरक्षा, समय की पाबंदी और कामकाज की क्षमता बनी रहे।

रेलवे, विमानन और हाईवे, तीनों क्षेत्रों में एआई का सबसे असरदार उपयोग ''प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस'' यानी पहले से खराबी का अंदाज़ा लगाकर रखरखाव करना है। पटरी, ट्रेन के डिब्बे, सिग्नल सिस्टम, पुल और विमान के हिस्सों से मिले डेटा का विश्लेषण करके एआई शुरुआती स्तर पर ही खराबी के संकेत पहचान लेता है। इससे हादसों का खतरा कम होता है, सेवाओं में रुकावट कम होती है और बुनियादी ढांचे की कुल लागत भी काफी कम हो जाती है।

इन सभी उपयोगों को आगे बढ़ाने में कुछ सहायक तकनीकें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे निरीक्षण को अपने – आप करने के लिए कंप्यूटर विज़न, जटिल परिवहन सिस्टम का डिजिटल मॉडल बनाने के लिए डिजिटल ट्विन, लगातार निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रियल – टाइम डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म।

ये सभी मिलकर परिवहन व्यवस्था को पुराने तरीके की बिखरी और समस्या आने के बाद कारवाई करने वाली प्रणाली से बदलकर, पहले से अनुमान लगाने वाली, आपस में जुड़ी हुई और समझदारी से चलने वाली प्रणाली बना रही हैं। यही बदलाव भारत के उस लक्ष्य का आधार है, जिसमें देश एक सुरक्षित, कुशल और दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने वाला परिवहन और लॉजिस्टिक्स तंत्र बनाना चाहता है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स को विशेष एआई विशेषज्ञों की जरूरत क्यों है

भारत रेलवे, एक्सप्रेसवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इसके लिए ऐसे पेशेवरों की जरूरत है, जिन्हें AI की तकनीक भी आती हो और परिवहन व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की वास्तविक सीमाओं और जरूरतों की समझ भी हो।

डॉ. विपुल मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर
गति शक्ति विश्वविद्यालय

इस बदलाव के केंद्र में ऐसे नए तरह के इंजीनियरों की मांग है, जो केवल एल्गोरिदम और डेटा ही नहीं जानते हों, बल्कि परिवहन नेटवर्क, सामान की आवाजाही और बुनियादी ढांचा प्रणालियों के काम करने के तरीके को भी अच्छी तरह समझते हों।

इस राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाएं तैयार करना है। यह देश का पहला विश्वविद्यालय है, जो केवल परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका शिक्षा मॉडल सामान्य इंजीनियरिंग पढ़ाई से आगे जाकर व्यावहारिक तकनीक, मल्टीमॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक्स की दक्षता और बड़े स्तर पर डेटा आधारित फैसलों पर ज़ोर देता है।

इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ताकत उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत जुड़ाव है।

रेलवे, हाईवे, बंदरगाह, विमानन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क बना रहता है, जिससे पढ़ाई वास्तविक समस्याओं से जुड़ी रहती है। इससे छात्रों को असली डेटा, मौजूदा सिस्टम और नई तकनीकों के साथ काम करने का मौका मिलता है। नतीजा यह होता है कि छात्र पढ़ाई को सीधे व्यवहार में बदल पाते हैं और करियर की शुरुआत से ही सार्थक योगदान दे पाते हैं।

मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स का भविष्य गढ़ना

अब एआई और डेटा साइंस कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं रह गए हैं, बल्कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स के भविष्य की बुनियाद बन चुके हैं। जैसे – जैसे भारत एकीकृत, तेज़, कुशल और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, वैसे – वैसे ऐसे कुशल लोगों की जरूरत और बढ़ेगी जो इन तकनीकों का सही इस्तेमाल कर सकें।

देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए विशेष और आधुनिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए गति शक्ति विश्वविद्यालय इस बदलाव की अगली कतार में खड़ा है। यह विश्वविद्यालय ऐसे इंजीनियर तैयार कर रहा है जो आने वाले समय के परिवहन सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, बेहतर बनाएंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। रूट प्लानिंग को बेहतर बनाना, राजस्व प्रबंधन और रखरखाव व सुरक्षा के लिए भविष्य का अनुमान लगाने वाली तकनीकों पर होने वाला उन्नत शोध, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की मजबूत नींव बनेगा।

महाशिवरात्रि भीतर के अंधकार से संवाद

राजन कुमार शर्मा

महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का वह क्षण है जहां आस्था, दर्शन और आत्मबोध एक साथ उपस्थित होते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व शिव – तत्त्व के स्मरण और साधना का अवसर है। वह शिव जो केवल संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन और कल्याण के अधिष्ठाता हैं। भारतीय परंपरा में शिव आदि और अनंत के प्रतीक माने गए हैं। उनका डमरु सृष्टि की लय का उद्घोष करता है, जटाओं से अवतरित गंगा करुणा का प्रतीक है और भस्म – विभूषण यह स्मरण कराता है कि भौतिकता अंततः नश्वर है।

परंतु महाशिवरात्रि का महत्व केवल प्रतीकों में नहीं, बल्कि उस आत्ममंथन में है जिसकी ओर यह पर्व संकेत करता है। यह रात जागरण की है, किंतु केवल आंखें खुली रखने की नहीं चेतना को जाग्रत रखने की है। यह कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मसंयम, मौन और अंतर्मुखी यात्रा का अवसर देती है। शिव यहां केवल पूजित देवता नहीं, बल्कि स्थिर, सजग और गहन चेतना के प्रतीक हैं।

आज के समय में जब समाज उपभोग, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन की अति से गुजर रहा है, शिव का योगी स्वरूप संयम और संतुलन का विकल्प प्रस्तुत करता है। आधुनिक जीवन की गति तीव्र है, परंतु उसकी लय अक्सर असंतुलित है। शिव का नटराज रूप हमें स्मरण कराता है कि गति आवश्यक है, पर लय के बिना वह विनाशकारी हो सकती है। जीवन का नृत्य तभी सुंदर है जब उसमें मर्यादा और संतुलन हो।

समकालीन भारत विशेष रूप से युवा है। ऊर्जा से भरपूर, महत्वाकांक्षी और निरंतर ऑनलाइन। विश्वविद्यालयों के गलियारों में डेडलाइन, प्लेसमेंट, प्रतियोगिता और भविष्य जैसे शब्द गूंजते हैं। तकनीक ने अवसरों के नए द्वार खोले हैं, पर इसके साथ एक स्थायी बेचैनी भी जन्मी है। तुलना की संस्कृति, सफलता की दौड़ और असफलता का भय युवा मन को निरंतर तनाव में रखता है। ऐसे समय में महाशिवरात्रि ठहराव का संकेत देती है।

शिव का मौन आज के शोरगुल भरे डिजिटल संसार के लिए एक चुनौती है। नोटिफिकेशन और एल्गोरिद्म के बीच घिरा मन निरंतर उत्तेजित है, पर स्थिर नहीं। महाशिवरात्रि पूछती है। क्या हम केवल कनेक्टेड हैं या सचमुच सचेत भी हैं? जागरण केवल रात्रि भर जगने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे दूर करने का प्रयास है।

शिव का दर्शन हमें एक असहज सत्य से परिचित कराता है। परिवर्तन के बिना सृजन संभव नहीं। जिस संहार को हम भय से देखते हैं, वही नवसृजन का आधार बनता है। जीवन में पुरानी आदतों, अहंकार और जड़ता का विसर्जन ही नए विचारों और ऊर्जा के लिए स्थान बनाता है। आज जब हम परिवर्तन से डरते हैं और सुविधा को स्थिरता समझ लेते हैं, शिव का स्मरण हमें साहस देता है कि हम आवश्यक बदलाव को स्वीकार करें।

महाशिवरात्रि का संदेश धर्म की आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और उत्तरदायित्व में निहित है। भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवनशैली है। शिव का वैराग्य पलायन नहीं, बल्कि विवेक है। यह जानने की क्षमता कि क्या आवश्यक है और क्या त्याज्य। यह संतुलन आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ उपलब्धियां बढ़ रही हैं पर मानसिक शांति घट रही है।

देशभर के शिवालयों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ केवल परंपरा का निर्वाह नहीं करती, वह सामूहिक चेतना की उस धारा को जीवित रखती है जहां व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है। मैं कौन हूं? मेरी दिशा क्या है? यह आत्मप्रश्न ही आध्यात्मिकता का आरंभ है।

आज भारत विकास की तीव्र यात्रा पर है। आर्थिक प्रगति और तकनीकी नवाचार हमारी पहचान बन रहे हैं। किंतु इस प्रगति के साथ मानसिक संतुलन और नैतिक स्थिरता का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। शक्ति और शांति, गति और विवेक इनका सहअस्तित्व ही पूर्णता है। शिव – तत्त्व इसी समन्वय का प्रतीक है।

महाशिवरात्रि हमें स्मरण कराती है कि अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी होता है। अज्ञान, अहंकार और असंतुलन ही वह छाया हैं जिनसे संवाद आवश्यक है। यह पर्व हमें इश्वर से अधिक स्वयं से जोड़ने का अवसर देता है। यदि समाज को स्थिरता और दिशा चाहिए, तो उसे साहस, करुणा और आत्मसंयम जैसे शिव – तत्त्वों को जीवन में उतारना होगा।

महाशिवरात्रि कोई एक रात्रि का उत्सव भर नहीं है। यह एक दृष्टि है। अपने भीतर झांकने की, अनावश्यक को त्यागने की और संतुलित जीवन की ओर बढ़ने की। जब तक हम भीतर से जाग्रत नहीं होंगे, बाहरी प्रकाश भी हमें पूर्ण नहीं कर पाएगा। यही इस पर्व की सार्वकालिक प्रासंगिकता है – भीतर के अंधकार से संवाद और चेतना के प्रकाश की ओर एक सतत यात्रा।

आरडीजी पर भाजपा अपना रुख स्पष्ट करे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा से स्पष्ट करने को कहा है कि वह प्रदेश को राजस्व

घाटा अनुदान (आरडीजी) मिलने के पक्ष में है या नहीं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरडीजी सरकार का नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता का अधिकार है और इसे बहाल करवाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा आरडीजी समाप्त किए जाने से हिमाचल को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सर्वदलीय बैठक में अन्य दलों ने राज्य सरकार का समर्थन किया, लेकिन भाजपा ने स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर आरडीजी बहाल करवाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूध पर समर्थन मूल्य देने के बाद अब अदरक पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा। सराहां अस्पताल में एक वर्ष के भीतर विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती और अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने की घोषणा करते हुए उन्होंने सराहां में सीबीएसई स्कूल खोलने तथा सराहां- चंडीगढ़ मार्ग को डबललेन करने की बात भी कही।

प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वाई. एस. परमार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 118 जैसे प्रावधानों से प्रदेश के हित सुरक्षित किए गए थे और वर्तमान सरकार भी उन्हीं पदचिन्हों पर चल रही है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच वर्षों में मिली अतिरिक्त राशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण प्रदेश पर भारी कर्ज और देनदारियां बढ़ीं।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा गुटों में बंटी नजर आई। उनके अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पहले अकेले वॉकआउट कर गए, जबकि अन्य विधायक कुछ समय तक बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

जनसभा में विधायक रीना कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पूर्व किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नई आवश्यक औषधि सूची एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट तैयार करने को कहा, जिसकी समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं की खरीद सीधे निर्माता कंपनियों से की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, आपूर्ति में देरी रुकेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने दवाओं की सैंपलिंग और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में समर्पित सेल स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में यह व्यवस्था शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और दवा निर्माता कंपनियों पर गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के दिए निर्देश, चनौर घटना पर जताया दुःख

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने देहरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चनौर स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील वर्कर सलोचना देवी की हत्या की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित स्थान होने चाहिए।

उन्होंने जानकारी दी कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कर उसे और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों, शिक्षकों, मिड-डे मील वर्करों तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा मंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि विभाग इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

आउटकम बजटिंग पर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। ''नोडल अधिकारियों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण : आउटकम बजटिंग के माध्यम से नीति को कार्य निष्पादन में रूपांतरित करना'' विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्रदेश सरकार की क्षमता निर्माण श्रृंखला 'नीति से परिणीति 2.0' के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विभागीय नियोजन प्रणालियों को सशक्त बनाना तथा नीतियों को मापनीय परिणामों में प्रभावी रूप से परिवर्तित करना है।

कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन सेल के सहयोग से तथा तकनीकी भागीदार के रूप में GIZ इण्डिया के सहयोग से किया गया।

योजना विभाग के सलाहकार डॉ. बसु सूद ने कहा कि आउटकम बजटिंग केवल वित्तीय प्रारूपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साक्ष्य-आधारित शासन, रणनीतिक योजना और प्रभावी परिणामों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विभागीय प्राथमिकताओं को ऐसे ठोस परिणामों से जोड़ने पर बल दिया, जो नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करें।

कार्यशाला में परिणाम-केंद्रित नियोजन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं, 'थ्योरी ऑफ चेंज' की अवधारणा तथा स्मार्ट संकेतकों के विकास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्र आयोजित किए गए। 'राज्यों के लिए नीति आयोग' विषय पर विशेष सत्र में राज्य स्तरीय संस्थागत क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।

डाटा-आधारित नियोजन एवं बजटिंग, निगरानी ढांचे की मजबूती तथा सतत विकास लक्ष्यों के साथ विभागीय योजनाओं के समन्वय पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों को राज्य बजट की संरचना, लक्ष्यों और प्रदर्शन मापन से उसके संबंध की समग्र जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में स्पष्ट किया गया कि आउटकम बजटिंग का उद्देश्य केवल व्यय पर नहीं, बल्कि व्यय से प्राप्त उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि सार्वजनिक धन को प्रभावी विकास निवेश में परिवर्तित किया जा सके और पारदर्शिता व जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सके।

पशु मित्रों की शारीरिक परीक्षा पर विभाग का स्पष्टीकरण सोशल मीडिया की खबरें भ्रामक

शिमला/शैल। पशुपालन विभाग ने पशु मित्रों की भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया में फैल रही खबरों को भ्रामक बताया है। विभागीय प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 को अधिसूचित पशु मित्र नीति, 2025 के तहत की जा रही है।

उन्होंने बताया कि शारीरिक परीक्षा केवल कार्यात्मक फिटनेस जांच है, ताकि चयनित अभ्यर्थी पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुपालन फार्मों में आवश्यक दायित्व सुरक्षित रूप से निभा सकें। इसमें लगभग 25 किलोग्राम वजन की बीमार भेड़ या बकरी को उठाना तथा चारे की बोरियां संभालना शामिल है। यह परीक्षा किसी प्रकार की सहनशक्ति प्रतियोगिता नहीं है और सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू है।

चार घंटे प्रतिदिन के अंशकालिक कार्य के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है। परीक्षा उप-मंडलाधिकारी (सिविल0 की अध्यक्षता वाली समिति की निगरानी में हो रही है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। अब तक 315 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और किसी चोट की सूचना नहीं है। विभाग ने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित है।

विश्व बैंक ने हिमाचल में आपदा प्रबंधन व पुनर्निर्माण के लिए 245 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी

शिमला/शैल। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने हिमाचल प्रदेश में चरम मौसम की घटनाओं से निपटने और अधिक सुदृढ़ अवसंरचना के निर्माण हेतु 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस परियोजना से राज्य के लगभग 23 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश अत्यधिक वर्षा और अन्य चरम मौसम घटनाओं से प्रभावित रहा है, जिससे लगभग 1 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ। वर्ष 2023 और 2025 के मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण जनहानि, आवास और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति, तथा स्कूलों, बाजारों और रोजगार तक पहुंच बाधित हुई। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में व्यवधान से कृषि और बागवानी उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

'रेज़िलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट' के तहत राज्य के आपदा-उपरांत पुनर्निर्माण प्रयासों को समर्थन दिया जाएगा तथा भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सुदृढ़ और टिकाऊ अवसंरचना के बेहतर नियोजन और डिजाइन पर कार्य किया जाएगा। इस परियोजना से एक मिलियन से अधिक महिलाओं को आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और कृषि, हस्तशिल्प तथा ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों में आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे। सामुदायिक स्वामित्व वाली इकाइयों में निवेश के माध्यम से लगभग 12,000 लोगों को नए या बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने और कारीगरों, उत्पादकों तथा किसानों के लिए नए बाजार संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

विश्व बैंक इंडिया के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर पॉल प्रोसी ने कहा कि सुदृढ़ विकास और रोजगार सृजन पर आधारित पहलें देशों को चरम मौसम की चुनौतियों के बीच भी दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 100 मिलियन डॉलर की निजी पूंजी को आपदा जोखिम वित्तपोषण और बीमा समाधानों की दिशा में आकर्षित करने में भी सहायक होगी।

फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एजेंसी फ्रांसेज़ डे डेवलपमेंट) के सहयोग से परियोजना के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) के माध्यम से 250 से अधिक पुलों, सड़कों और फुटब्रिजों के पुनर्वास सहित टिकाऊ अवसंरचना निर्माण में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा, जिससे एक मिलियन से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

परियोजना के टास्क टीम लीडर्स अनुप करंथ और मेलानी एस. कप्पेस ने कहा कि यह पहल वर्तमान पुनर्प्राप्ति के साथ भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ढलानों की स्थिरता, परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता प्रणालियों की बहाली और जोखिम विश्लेषण के माध्यम से समुदायों को सुरक्षित और सशक्त बनाया जाएगा। 245 मिलियन डॉलर की परियोजना की कुल अवधि 16 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें 3.5 वर्ष की मोहलत अवधि शामिल है।

अनुसंधान एवं प्रसार उत्कृष्टता के लिए केवीके किन्नौर को सर्वश्रेष्ठ केवीके पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किन्नौर को फार्म

एंड फूड द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह में 'सर्वश्रेष्ठ केवीके पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जिले में प्राकृतिक खेती के प्रभावी प्रचार-प्रसार और बड़े स्तर पर अपनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया।

समारोह किसान चौंबर, मोहाली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर केवीके के कीट विज्ञानी डॉ. बुधि राम को देशी मधुमक्खियों के संरक्षण हेतु इको-हाइव तकनीक के लिए 'सर्वश्रेष्ठ युवा शोधकर्ता' पुरस्कार मिला, जबकि किसान आशीष नेगी को जैविक फल उत्पादों के विपणन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'सर्वश्रेष्ठ किसान' पुरस्कार प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने इसे प्रभावी अनुसंधान एवं प्रसार कार्य का परिणाम बताया और पूरी टीम को बधाई दी।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए केंद्र की बहुआयामी पहल

शिमला/शैल। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में बताया कि पर्यटन स्थलों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है।

केंद्र सरकार 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' 9तीर्थस्थल पुनरुद्धार) जैसी योजनाओं के तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। स्वदेश दर्शन योजना को अब 'स्वदेश दर्शन 2.0' के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है। इसके अंतर्गत 'चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट' उप-योजना भी लागू की गई है। इसके अलावा 'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' के तहत वैश्विक स्तर के आइकॉनिक पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय 'डोमेस्टिक प्रमोशन एंड पब्लिसिटी' योजना के तहत मेलों, उत्सवों और पर्यटन आयोजनों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता देता है। 'असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसिज' योजना के माध्यम से आईटीडीसी, एएसआई और रेलवे जैसे केंद्रीय निकायों को भी पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए सहयोग दिया जाता है।

रोजगार सृजन के उद्देश्य से 'कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स' योजना लागू है, जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण और प्रमाणन दिया जाता है। साहसिक और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार की गई हैं। बजट 2025-26 में होमस्टे स्थापित करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा ऋण की भी घोषणा की गई है।

ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यटन रणनीति और रोडमैप' तैयार किया गया है, जिसमें क्लस्टर विकास, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विपणन सहयोग और क्षमता निर्माण पर जोर है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके अतिरिक्त 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' प्रतियोगिता के माध्यम से अब तक 71 गांवों को सम्मानित किया जा चुका है।

बिजली महादेव रोपवे निर्माण कार्य बंद

आयुष्मान योजना से 5.32 लाख परिवार लाभान्वित

शिमला/शैल। कुल्लू जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिजली महादेव में प्रस्तावित रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य स्थानीय विरोध के चलते जुलाई 2025 से बंद पड़ा है। यह जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नतिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को संसद में दी। उन्होंने बताया कि 272 करोड़ रुपये लागत की यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत अवार्ड की गई है और इसके लिए वन स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

मंत्री ने बताया कि स्थानीय नागरिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों का हवाला देते हुए परियोजना का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान रोपवे निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से निर्माण कार्य रोकना पड़ा।

इधर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संसद में जानकारी दी कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.32 लाख परिवारों को कवर किया गया है। राज्य में लाभार्थियों को 13.68 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा और चंबा जिलों में कुल 73 सरकारी और निजी अस्पताल योजना के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें कांगड़ा में 24 सरकारी और 36 निजी अस्पताल, जबकि चंबा में 8 सरकारी और 5 निजी अस्पताल शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को पहले से मौजूद बीमारियों सहित सालाना 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों ही मामलों में आवश्यक सहयोग और समन्वय के माध्यम से आगे की कारवाई की जाएगी।

हिमाचल भवन/सदन, नई दिल्ली के रेस्टोरेंट में मूल हिमाचलियों से ओवरचार्जिंग रोकने की मांग

शिमला/शैल। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर हिमाचल भवन/हिमाचल सदन के रेस्टोरेंट में मूल हिमाचलियों से कथित रूप से वसूले जा रहे कमर्शियल रेट पर रोक लगाने की मांग की है।

सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की वोल्वो बसें सुबह यात्रियों को हिमाचल भवन, नई दिल्ली के बाहर उतारती हैं। यात्री चाय और नाश्ते के लिए भवन के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित रेस्टोरेंट में उनसे कमर्शियल दरें वसूली जाती हैं। उनका कहना है कि ये दरें सरकारी दरों से दोगुनी या उससे अधिक हैं और आमतौर पर बाहरी व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई हैं।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब इस विषय में रेस्टोरेंट प्रबंधन से बात की जाती है तो उनका तर्क होता है कि सरकारी दरें केवल उन अतिथियों पर लागू होती हैं जो भवन के कमरों में ठहरे होते हैं, जबकि अन्य सभी ग्राहकों से कमर्शियल रेट ही लिया जाता है, चाहे वे हिमाचली हों या अन्य राज्यों के। सांसद ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों के भवनों में वहां के मूल निवासियों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मूल हिमाचलियों से सरकारी दरों पर ही शुल्क लिया जाए। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या हिमाचल प्रदेश के किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र को मान्य किया जाए। साथ ही, उन्होंने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

इस बीच 'फ्रेंड्स ऑफ हिमाचल' के पैट्रन इंद्र सिंह चंदेल ने भी रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मूल हिमाचलियों के साथ कथित भेदभाव की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों को भोजन परोसने में उपेक्षा बरती जाती है और बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जा रहे शुल्क को अनुचित करार दिया।

चंदेल ने हरियाणा की तर्ज पर राज्य के पत्रकारों को खानपान की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आतिथ्य व्यय का ऑडिट कराने तथा सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

बजट 2026-27 कृषि और ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित : अनुराग ठाकुर

शिमला। अनुराग सिंह ठाकुर ने बजट 2026-27 को किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.30 लाख करोड़ रूपये से अधिक तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1.62 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास के तहत 'विकसित भारत जी राम जी' योजना के लिए लगभग 1.51 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान है, जबकि मनरेगा में केंद्र का हिस्सा बढ़ाकर 95,692 करोड़ रूपये से अधिक किया गया है। पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत 55,900 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे दी जाएगी।

कृषि अनुसंधान के लिए 9,967 करोड़ रूपये, उर्वरक सब्सिडी हेतु 1.70 लाख करोड रूपये तथा पीएम-किसान के लिए 63,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही फसल बीमा, एमएसपी समर्थन, कृषि अवसंरचना निधि और 10,000 एफपीओ कार्यक्रम को जारी रखा गया है।

उन्होंने कहा कि 'भारत-VISTAAR' नामक एआई-आधारित मंच के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किसानों को वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मेडिकल कॉलेजों पर केंद्र का जवाब राज्य सरकार पर आरोप:सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। सुरेश कुमार कश्यप ने लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उत्तर का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार पर मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को लेकर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। चंबा, हमीरपुर और नाहन के मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं, जबकि सिरमौर मेडिकल कॉलेज परियोजना ठेकेदार और एजेंसी विवाद के कारण प्रभावित बताई गई है।

कश्यप ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने लगभग 283 करोड़ रुपये का राज्यांश अब तक जमा नहीं किया, जिससे परियोजना में देरी हुई है। उन्होंने मांग की कि लंबित राशि शीघ्र जारी कर मेडिकल कॉलेज का निर्माण तय समयसीमा में पूरा किया जाए।

हिमाचल में रेल विस्तार को मिला 2,716 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन का विस्तार पर सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा लोकसभा में पुछे गये प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी की केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में 2,716 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

1 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 17,622 करोड़ रुपये की लागत से 214 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनें स्वीकृत हैं। इनमें से 64 किलोमीटर लाइन चालू की जा चुकी है तथा मार्च 2025 तक 8,280 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। नंगल डैम-ऊना-अंदौरा- दौलतपुर चौक (60 किमी) खंड का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि दौलतपुर चौक से तलवाड़ा (52 किमी) खंड पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 1,540 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़-बद्दी (28 किमी) नई रेल लाइन पर भी कार्य आरंभ कर दिया गया है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) रेल लाइन परियोजना 6,753 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत है, जिसमें 75 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, परंतु अब तक 82 हेक्टेयर भूमि ही उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार को 2,781 करोड़ रुपये का अंशदान देना था, जबकि अब तक 847 करोड़ रुपये ही जमा किए गए हैं। शेष राशि के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

बेंगलुरु में शादी समारोह में पहली बार दिखा मैकेनिकल हाथी

शिमला/शैल। बेंगलुरु में आयोजित एक भव्य विवाह समारोह में पहली बार मैकेनिकल (कृत्रिम) हाथी का उपयोग किया गया, जिसने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। दक्षिण भारत में शादियों और धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी को शुभता, समृद्धि और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में जीवित हाथियों को शामिल किया जाता रहा है, लेकिन पशु कल्याण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समारोह में आधुनिक तकनीक से तैयार मैकेनिकल हाथी को शामिल किया गया।

प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने भी इस अनोखी पहल की सराहना की। उन्होंने इसे बेहद सुंदर और अद्भुत मानवीय रचना बताते हुए कहा कि ऐसे नवाचारों से बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिपूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं।

पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट पॉलिसी खुशबू गुप्ता ने कहा कि शादियों में उपयोग किए जाने वाले हाथियों को अकसर भय और शारीरिक दंड के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिससे उन्हें भारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल हाथी एक संवेदनशील और सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे पशु-क्रूरता रोकी जा सकती है।

उन्होने बताया कि यह मैकेनिकल हाथी करीब 3 मीटर ऊंचा और इसका वजन 500 किलोग्राम है। यह केरल के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। यह रबर, फाइबर, धातु, फोम और स्टील से बना है तथा पांच मोटरों से संचालित होता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह सिर, कान, आंख और पूंछ हिला सकता है, सूंड उठा सकता है और पानी की फुहार भी छोड़ सकता है। इसे बिजली से संचालित किया जाता है और जुलूसों में आसानी से ले जाया जा सकता है।

यह पहल पारंपरिक आयोजनों में पशु-हित और आधुनिक तकनीक के संतुलन की नई मिसाल के रूप में देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस पहल की चर्चा हो रही है और कई लोगों ने इसे भविष्य के आयोजनों के लिए एक प्रेरक मॉडल बताया है।

410 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा शुरू

शिमला/शैल। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मसानी चंद्र शेखर ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि भारतनेट के प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत देश की 2,22,341 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जानी हैं, जिनमें से 2,14,904 पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि इन चरणों में हिमाचल प्रदेश की 410 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं दी गई हैं। योजना के तहत सर्वाधिक 35,746 पंचायतें उत्तर प्रदेश में कनेक्ट की गई हैं, जबकि गोवा की किसी भी पंचायत को अब तक यह सुविधा नहीं मिली है।

इसी प्रकार हरियाणा की 6,082, उत्तराखंड की 1,993, पंजाब की 12,668, जम्मू और कश्मीर की 1,101 तथा चंडीगढ़ की 12 पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की गई हैं।

मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक 783 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 630 करोड़ रुपये का बजट

शिमला/शैल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने सांसद इंदु बाला गोस्वामी को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 630 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

उन्होंने बताया कि यह मांग-आधारित योजना है, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। देशभर से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और पात्र परियोजनाओं को मेरिट के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बिंदल के आरोपों से विकास कार्यों की रफ्तार पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति और विकास की गति को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता में राज्य की कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाये। उनका कहना है कि पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्यो की रफ्तार अपेक्षित स्तर पर नहीं है और सरकार वित्तीय संकट का वातावरण बनाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि वित्त विभाग की आधिकारिक प्रस्तुति के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाकर लगभग 0.830% से 0.914% कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में प्रदेश को लगभग 13,950 करोड़ रूपये प्राप्त होंगे, जो पिछले वर्ष से लगभग 2,450 करोड़ रूपये अधिक हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी विकास मद में लगभग 4,179 करोड़ रूपये तथा SDRF और DMF मद में लगभग 2,682 करोड़ रूपये मिलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राज्य सरकार के अपने दस्तावेजों के हैं।

उन्होंने वित्त आयोग के ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि छठा वित्त आयोग (1974-79) में 161 करोड रूपये, 11वां वित्त आयोग (2001-05) में 1,979 करोड़ रूपये, 12वां वित्त आयोग में 10,202 करोड़ रूपये, 13वां वित्त आयोग में 7,889 करोड़ रूपये जबकि केंद्र में वर्तमान शासनकाल के दौरान 14वां वित्त आयोग में लगभग 40,624 करोड़ रूपये, 15वां वित्त आयोग में लगभग 48,000 करोड़ रूपये की सहायता प्रदेश को मिली। उन्होंने कहा कि यह तुलना स्पष्ट करती है कि वर्तमान समय में हिमाचल को पूर्ववर्ती वर्षो की तुलना में कई गुना अधिक संसाधन प्राप्त हुए हैं।

राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के संदर्भ में उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच लगभग 18,091 करोड़ रूपये मिले, जबकि 2015 से 2025 के बीच यह राशि बढ़कर लगभग 89,254 करोड़ रूपये हो गई। उन्होंने कहा कि केवल वर्तमान राज्य सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में ही लगभग 27,000 करोड़ रूपये विभिन्न मदों में प्राप्त हुए, फिर भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का वातावरण बना रही है।

इन आंकड़ों के आधार पर भाजपा का तर्क है कि राज्य में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता निर्धारण और व्यय प्रबंधन में खामियां हैं। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि पर्याप्त आर्थिक सहयोग के बावजूद प्रदेश में कुछ संस्थानों को बंद किया गया, कर्मचारियों के भत्तों और पेंशन भुगतान में देरी हुई तथा करों और शुल्कों में वृद्धि कर आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। उन्होंने सीमेंट, डीजल, बिजली दरों और बस किराए में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए इसे आम जनता की जेब पर सीधा प्रभाव बताया।

डॉ. बिंदल ने राज्य के राजकोषीय आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आय लगभग 42,000 करोड़ रूपये और व्यय लगभग 48,000 करोड़ रूपये है, यानी लगभग 6,000 करोड़ रूपये का अंतर है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की आय बढ़कर लगभग 26,600 करोड़ रूपये (राज्य के स्वयं के राजस्व के रूप में) होने का अनुमान है, जिससे यह अंतर स्वत: कम हो सकता है। ऐसे में वित्तीय आपातस्थिति जैसा माहौल बनाना तथ्यों से परे है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं, टैक्स डिवोल्यूशन, विश्व बैंक सहायता, नाबार्ड फंडिंग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य अवसंरचना योजनाओं सहित प्रदेश को लगभग 2.12 लाख करोड़ रूपये की कुल सहायता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त लगभग 46,000 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग और फोरलेन परियोजनाएं चल रही हैं तथा लगभग 6,000 करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजमार्ग रखरखाव पर खर्च किए जा रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की परियोजनाएं इससे अलग हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना के लिए 12.2 लाख करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश पर्यटन, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करके उठा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह राजनीतिक आरोपों की बजाये परियोजनाओं की तैयारी, निवेश आकर्षण और प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान दे।

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियां जटिल होती हैं। सीमित संसाधन, भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और कर्मचारियों पर उच्च व्यय संरचना राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ऐसे में केवल केंद्रीय सहायता की मात्रा के आधार पर समग्र स्थिति का आकलन करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

सर्वदलीय बैठक को लेकर भी भाजपा ने सवाल उठाये हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि बैठक में सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेता अनुपस्थित रहे, जिससे इसकी गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगता है। उनका आरोप है कि यदि सरकार वास्तविक समाधान चाहती तो व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करती।

समग्र रूप से देखें तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर राजनीतिक मतभेद स्पष्ट हैं। एक पक्ष केंद्रीय सहायता और वित्त आयोग के आंकड़ों के आधार पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष संरचनात्मक चुनौतियों और परिस्थितिजन्य दबावों को प्रमुख कारण मानता है। आने वाले बजट और नीतिगत निर्णय यह स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है।

क्या प्रदेश वित्तीय आपात

....पृष्ठ 1 का शेष

बारे में पूछ रहे हैं जिसे उसके खिलाफ चल रही जांच को बन्द न करने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले दिनों में और भी सामने आयेंगे। ऐसे परिदृश्य में यदि राजस्व घाटा अनुदान बहाल न हो पाया तो सरकार कैसे चलेगी। पिछली देनदारियां कैसे पूरी होगी? अभी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में वित्त आयोग पर सरकार के खुलासे को अपने शब्द नहीं दिये हैं। इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या रहती है और सरकार का आचरण क्या रहता है यह सब आने वाले दिनों में सामने आयेगा? क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान बहाल न होने पर सरकार के खर्चे कैसे चलेंगे यह सवाल अपनी जगह खड़ा रह जाता है। क्योंकि वित्त सचिव ने जो कुछ अपनी प्रस्तुति में कहा है वह कोई राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि एकदम कड़वा सच है। वित्त सचिव के खुलासे पर अमल करने के लिये प्रदेश में वित्तीय आपात लागू करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि वित्तीय आपात की स्थिति में भी वित्तीय लाभों पर कैंची चलाई जा सकती है। राष्ट्रपति शासन में सारी राजनीतिक नियुक्तियां स्वत: ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में यदि सही में प्रदेश के वित्तीय हालत खराब हैं तो देर-सवेर प्रदेश को इन विकल्पों पर लाना ही होगा।

आरडीजी मुद्दे पर कांग्रेस का अनुराग ठाकुर को खुला चैलेंज

शिमला/शैल। कांग्रेस ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के मुद्दे पर प्रदेश की जनता को गुमराह न करने की नसीहत दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि अनुराग ठाकुर का यह दावा निराधार है कि केंद्र सरकार ने बीस वर्ष पहले ही आरडीजी बन्द करने का निर्णय ले लिया था। यदि ऐसा है तो वे संबंधित चिट्ठी सार्वजनिक करें।

मंत्रियों ने कहा कि आरडीजी हिमाचल का संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रावधानित है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने भाजपा पर पूर्व कार्यकाल में आर्थिक कुप्रबंधन और फिजूलखर्ची के आरोप लगाते हुये कहा कि राज्य को कर्ज के दलदल में धकेलने के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है।

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश को लगभग 70,000 करोड़ रुपये (54,000 करोड़ आरडीजी और 16,000 करोड़ जीएसटी मुआवजा) मिले, लेकिन संसाधनों का उपयोग विकास के बजाये चहेतों को लाभ पहुंचाने में हुआ। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने कई भवन खाली पड़े हैं और नालागढ़ में उद्योगपतियों को रियायती दरों पर भूमि व अन्य रियायतें दी गई।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षो में 17,000 करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में मिले हैं, बावजूद इसके वित्तीय अनुशासन बनाये रखते हुए 26,683 करोड़ रुपये संसाधन जुटाए गए और 26,000 करोड़ रुपये ऋण व ब्याज का भुगतान किया गया। मंत्रियों ने भाजपा से आरडीजी पर अपना स्पष्ट रुख प्रदेश की जनता के सामने रखने की मांग की।

क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

.....पृष्ठ 1 का शेष

वर्ष की आयु पर एक बेलदार को सेवानिवृत्ति किये जाने का आदेश सामने आने के बाद सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह चर्चा चल रही है कि एक ही सरकार के दो विभागों में अलग-अलग सेवानिवृत्ति नियम कैसे हो सकते हैं। 2024 में आये उच्च न्यायालय के फैसले की शिक्षा विभाग को जानकारी न होने से सरकार की कार्यप्रणाली सवालों में आ गयी है।